भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 247

21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **इलेक्ट्रॉनिक-राष्ट्रीय कृषि बाजार और संबद्ध प्लेटफॉर्मों का विस्तार**

247. श्री काली चरण सिंहः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री अरुण गोविलः
श्री शशांक मणिः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2026 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और संबद्ध प्लेटफॉर्मों के विस्तार और एकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एकीकृत की गई मंडियों और राज्यों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार और मूल्य खोज तंत्र में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष रूप से मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसानों की लाभकारी बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और विचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार कृषि उत्पादों के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाने के लिए देशभर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, 'नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट' (ई-नाम) कार्यान्वयन कर रही है। ई-नाम पर मंडियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से मिले प्रस्तावों के आधार पर एकीकृत किया जाता है। जनवरी से जून 2026 के बीच, 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 134 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है।

(ख): 30 जून 2026 तक, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1656 मंडियों को ई-नाम से एकीकृत किया जा चुका है।

(ग) और (घ): सरकार ने किसानों की अच्छी कीमत देने वाले बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाने और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म से एकीकृत मंडियाँ किसानों को ज़्यादा खरीदारों तक पहुँच, पारदर्शी ऑनलाइन बोली-प्रक्रिया, बेहतर कीमत तय होने की सुविधा और बिक्री से मिली रकम का सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान की सुविधा देती हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर के खरीदारों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली-प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाकर राज्यों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा देता है, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमत तय होने और किसानों को बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश में मेरठ और उससे सटे ज़िलों हापुड़, गाज़ियाबाद, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर और अमरोहा में 9 मंडियों को ई-नाम से एकीकृत किया गया है।

जून 2026 तक, ई-नाम पर लगभग ₹83.95 करोड़ मूल्य के 28,566 मीट्रिक टन का अंतर-राज्यीय व्यापार दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, विभाग '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम' के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दे रहा है, इसका उदेश्य किसानों की सामूहिक मार्केटिंग को मज़बूत करना, वैल्यू चेन पार्टनर्स, संगठित रिटेलर्स, संस्थागत खरीदारों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ मार्केट लिंकेज को बेहतर बनाना और बेहतर मोल-भाव की क्षमता और बड़े पैमाने पर काम करने के फ़ायदों के लिए उपज को एक साथ इकट्ठा करने में मदद करना है।

मेरठ, हापुड़, गाज़ियाबाद, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर और अमरोहा में 62 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें 43,226 किसान सदस्य हैं।

*****